आज ही के दिन 1942 में जापानी फौजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के रंगून शहर पर कब्जा किया था।

यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग

जसपुर। सवर्ण समाज उत्थान समिति की बैठक में यूजीसी काले कानून पर विरोध व्यक्त किया गया और यूजीसी काले कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई। यूजीसी का विरोध किये जाने के संबंध में रणनीति बनाई गई, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जसपुर में सवर्ण समाज उत्थान समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन धर्मशाला मंदिर के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। वक्ताओं ने यूजीसी कानून को काले कानून की संज्ञा देते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही 8 मार्च को दिल्ली में यूजीसी के विरोध में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने का आह्वान किया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूजीसी काले कानून का विरोध व्यक्त किए जाने हेतु जसपुर के मुख्य मार्गों पर फ्लेक्सी बैनर लगाए जाएंगे तथा जसपुर क्षेत्र में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को यूजीसी के विरोध में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य गहलोत, अंकुर बंसल आदि थे।

'इंडियाज़ ऑनेस्ट इंडिपेंडेंस ऑनर' से सम्मानित होंगे राजपाल लेघा

- खनन निदेशक के रूप में कई सख्त कदम उठाकर किया सराहनीय कार्य
- उत्तराखंड की 'खनन नीति 2023' तैयार करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

भास्कर पोखरियाल (दैनिक भास्कर)

देहरादून/रुद्रपुर। उत्तराखंड में खनन व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। प्रदेश के खनन निदेशक राजपाल लेघा को उनके नेतृत्व में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित 'इंडियाज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंस ऑनर' से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 28 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जिलों हरिद्वार सहित तमाम जिलों में रहते हुए उन्होंने राजस्व को बड़ा लाभ देते हुए इसमें बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जैसे अतिसंवेदनशील जिलों का प्रभार राजपाल लेघा के पास था। उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाओं के दौरान ईमानदार अधिकारी के रूप में कार्य किया। खनन माफियाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर उनकी एक इंटरनल टीम लगातार काम करती रही है।

राजपाल लेघा के नेतृत्व में खनन विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे प्रदेश की खनन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनी है। अवैध खनन पर नियंत्रण, प्रक्रियाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों से विभाग की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

हाल ही में खनन क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के चलते धामी सरकार को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। इसे प्रदेश में खनन व्यवस्था में किए गए सुधारों का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।

वरिष्ठ उद्योगपति हरीश ने दी बधाई

रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार में खनन के मामले में इस बार हुए भारी राजस्व को लेकर जमकर प्रशंसा हो रही है। इसी मामले में सरकार और स्थानीय उद्योगपति भी काफी उत्साहित हैं। राजपाल लेघा द्वारा बनाई गई खनन नीतियाa प्रदेश में खनन व्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में किए गए नीतिगत बदलावों से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्पष्टता बढ़ी है। वरिष्ठ उद्योगपति हरीश मुंजाल ने कहा कि इन सुधारों से उद्योग जगत को भी एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था मिली है, जिससे खनन से जुड़े कार्य अधिक सुचारु रूप से संचालित हो पा रहे हैं। ईमानदारी और सुधार की सोच के साथ किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज राजपाल लेघा को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इन सुधारों से न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था की दिशा में भी उत्तराखंड एक उदाहरण बनकर उभर रहा है।

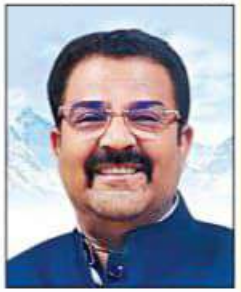

खनन निदेशक को सम्मान मिलने पर एसोसिएशन ने जताई खुशी

रुद्रपुर। उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा को खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर इंडियांज आनेस्ट इंडिपेन्डेंस ऑनर मिलने पर कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिऐशन एवं सितारगंज स्टोन क्रेशर एसोसिऐशन ने खुशी जताई है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में राजपाल लेखा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में में खनन विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे प्रदेश की खनन व्यवस्था सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनी है। उनके द्वारा ई-गवर्नेंसिंग डिजिटलाईजेशन होने से व्यापार में इजाफा हुआ है और राजस्व ग्रोथ बढी है। उनके द्वारा अवैध खनन पर नियंत्रण प्रक्रियाओं में सुधार और आधुनिक तकनीकी के उपयोग से खनन में सकारात्मक बदलाव हुए है जिससे राजस्व में बृद्दि के साथ साथ व्यवसाईयों को भी लाभ मिल रहा है उनके इन सुधारों से पूर्व में आधे से अधिक क्रेशर जो बन्द हो गये थे अवः पुनः चालू हो गये है। स्टोन क्रशिंग उद्योग उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें रॉयल्टी, फारेस्ट ट्रांजिट, जीएसटी, आयकर, आरटीओ आदि से टैक्स के मद में भी हजारों करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही 2 से 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला हुआ है। इससे मिनरल की मार्केट, जो पहले सिकुड़कर छोटी हो रही थी, अब इसका रिफॉर्म हो रहा है। खनन निदेशक राजपाल लेघा को इंडियांज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंस ऑनर सम्मान मिलने पर एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यों में एलएससी इन्फ्राटेक लिमिटेड, विन्ध्यवासिनी स्टोन क्रेशर, पाल स्टोन इंडस्ट्रीज, सुभाष स्टोन क्रेशर, जगदंबा स्टोन क्रेशर, विनोद स्टोन क्रेशर, सागर स्टोन क्रेशर, हिमालया स्टोन इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी स्टोन कम्पनी, श्री बालाजी स्टोन कंपनी, उत्तराखंड स्टोन कंपनी, जयश्री राम स्टोन क्रेशर, महालक्ष्मी स्टोन कंपनी, शुभम स्टोन कंपनी, कामाख्या स्टोन कंपनी, सितारगंज स्टोन कंपनी, राधे सोल्यूशन, बरेली स्टोन कंपनी, मॉर्डन ग्रिट्स इंडस्ट्रीज, भगवती स्टोन इंडस्ट्रीज, देवभूमि स्टोन इंडस्ट्रीज आदि ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।